शिव शक्ति को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, नागपुर

बनाम

मैसर्स स्वराज डेवलपर्स और अन्य।

17 अप्रैल 2003

[शिवाराज वी. पाटिल और अरिजित पसाया टी, जे.जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-धारा 115- संशोधन- वाद या अन्य कार्यवाहीयो में - अंतरिम आदेश- पुनरीक्षण याचिका -की पोषणीयता- का निष्कासन- अभिनिधारित किया गया: विधायी मंशा यह है कि अंतरिम आदेश धारा 115 के तहत पुनरीक्षण का विषय नहीं हो सकते हैं- इसलिए पुनरीक्षण याचिका कायम रखने योग्य नहीं - संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, किसी भी व्यक्ति को प्रक्रिया के दौरान अधिकार नहीं है, बल्कि केवल निर्धारित तरीके से आगे बढ़ने का अधिकार है - यदि वैधानिक परिवर्तन द्वारा प्रक्रिया का तरीका बदल दिया जाता है तो पार्टियों को बदले हुए तरीके के अनुसार आगे बढ़ना होता है, बिना किसी अपवाद के, जब तक कि कोई अलग शर्त न हो -धारा 6 सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897, रिविजन विधि धारा 115- पर लागू नहीं होती क्योंकि पक्षकारो को कोई मूल अधिकार उपलब्ध नहीं कराती है।

क़ानून की व्याख्या:

विधायी मंशा -इसे इस्तेमाल की गई भाषा से समझा जाना है- विधायी निर्माण के समर्थन के लिए शब्दों को जोडने, हटाये जाने की आवश्यकता या जिसके परिणामस्वरूप शब्दों को निरर्थक मानकर अस्वीकार कर दिया जाता है.

निर्माण के सिद्धांत- Casus omissus और क़ानून को संपूर्ण रूप से पढ़ना- विचार-विनमय किया गया।

विधिक सूक्तियाँ :

"Ad ed quae frequentius accidunt jura adaptantur" -

शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ:

अपील- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 का अर्थ सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 12(i) द्वारा संशोधित किया गया था। अपीलकर्ताओं ने अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने माना कि संशोधित धारा 115 के कारण पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि यदि पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले पक्ष के पक्ष में आदेश पारित किया गया होता, तो अंततः मुकदमे या अन्य

कार्यवाही का निपटारा नहीं होता। इसलिए वर्तमान अपील.

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका को सुनवाई योग्य न मानकर उसका निपटारा करने में गलती की है क्योंकि संशोधित प्रावधान उन याचिकाओं पर लागू नहीं होते हैं जो संशोधन से पहले स्वीकार की गई थीं; अपील और पुनरीक्षण एक समानांतर आधार पर खड़े हैं और अपीलकर्ता/आवेदक में निहित अधिकार हैं और इस प्रकार संशोधित प्रावधानों का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा; निषेधाज्ञा के लिए आवेदन और संशोधन की विषय-वस्तु का निर्माण 'अन्य कार्यवाही' अभिव्यक्ति से संबंधित है और यदि संशोधित प्रावधान लागू होते हैं, तो भी पुनरीक्षण याचिका के निपटान का मतलब ऐसी 'अन्य कार्यवाही' की अंतिम बर्खास्तगी होगा; संशोधन अधिनियम की धारा 32(2)(i), कोई अर्थ नहीं रखती है; विधायिका ने हमेशा सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के संदर्भ में लंबित कार्यवाही को बचाया है और इसलिए, संशोधन की तारीख पर उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही स्पष्ट रूप से संशोधन के प्रभाव से बाहर है; और भले ही तर्कों के लिए यह मान लिया जाए कि उस संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, यह स्पष्ट रूप से "कैसस ऑमिसस" का मामला है।

प्रतिउत्तरदाता ने तर्क दिया कि किसी क़ानून के प्रावधानों के सामान्य अर्थ को पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए और जब भी विधायिका

द्वारा लंबित कार्यवाही को संशोधित प्रावधानों के दायरे से बाहर रखने का इरादा रखती है, तो यह विशेष रूप से प्रदान किया गया था।

न्यायालय द्वारा अपील को खारिज करते हुये अभिनिर्धारित किया गया

1.1 पुनरीक्षण आवेदनों की अनुरक्षणीयता के बारे में उच्च न्यायालयों का निष्कर्ष सही था।

1.2. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 115 के तहत सवाल यह है कि क्या पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में आदेश से मुकदमे या अन्य कार्यवाही अंतिम रूप से निस्तारिण होती है, यदि उत्तर 'हां' है तो पुनरीक्षण कायम रखने योग्य है, लेकिन इसके विपरीत, यदि उत्तर 'नहीं' है तो पुनरीक्षण पोषणीय नहीं है। इसलिए, यदि आक्षेपित आदेश अंतरिम प्रकृति का है या अंतिम रूप से मामले का निर्णय नहीं करता है, तो पुनरीक्षण पोषणीय नहीं होगा। विधायी मंशा एकदम स्पष्ट है। वे आदेश, जो प्रकृति में अंतरिम हैं, वे धारा 115 के तहत रिविजन का विषय नहीं हो सकते हैं। पुराने संशोधन अधिनियम की धारा 97(3) और संशोधन अधिनियम की धारा 32(2)(i) की भाषा में उल्लेखनीय अंतर है। जबकि पूर्व में, संशोधन लागू होने से पहले स्वीकृत या लंबित आवेदनों को बचाने का स्पष्ट विधायी इरादा था, धारा 32(2)(i) में ऐसा इरादा महत्वपूर्ण रूप से अनुपस्थित है। संशोधन प्रक्रियाओं से संबंधित है।

किसी भी व्यक्ति के पास प्रक्रिया से संबधित अधिकार निहित नहीं है। उसे केवल निर्धारित प्रक्रिया से आगे बढ़ने का अधिकार है। यदि वैधानिक परिवर्तन द्वारा प्रक्रिया के तरीके में बदलाव किया जाता है, तो पार्टियों को बिना किसी अपवाद के, बदले हुए तरीके के अनुसार आगे बढ़ना होगा, जब तक कि कोई अलग शर्त न हो।

2. सामान्य खण्ड अधिनियम की धारा 6 लागू किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि संहिता की धारा 115 के तहत संशोधन की मांग करने वाले पक्ष में कोई भी वास्तविक हक-अधिकार निहित नहीं है।

3.1. ऐसे मामले में जहां क़ानून के एक विशेष प्रावधान हटा दिया गया है और उसके स्थान पर लंबित कार्यवाही के पक्ष में बचत खंड के बिना उसी आकस्मिकता से निपटने वाला एक अेार प्रावधान पेश किया गया है, तो यह उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि विधायिका का इरादा यह है कि लंबित कार्यवाही जारी रहेगी लेकिन नए प्रावधान के तहत उसी उद्देश्य के लिए नई कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

3.2. कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय किसी ऐसे वैधानिक प्रावधान में कुछ भी नहीं पढ़ सकता है जो स्पष्ट और स्पष्ट हो। क़ानून विधायिका का एक आदेश है। किसी क़ानून में प्रयुक्त भाषा विधायी मंशा का निर्धारक कारक है। शब्द और वाक्यांश ऐसे प्रतीक हैं जो सन्दर्भों के प्रति मानसिक सन्दर्भों की अेार इंशारा करते हैं। किसी

क़ानून की व्याख्या करने का उद्देश्य इसे अधिनियमित करने वाले विधानमंडल के उद्देश्य का पता लगाना है। विधायिका का इरादा मुख्य रूप से इस्तेमाल की गई भाषा से पता चलता है, जिसका अर्थ है कि जो कहा गया है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और जो नहीं कहा गया है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, जिस निर्माण के लिए शब्दों के समर्थन, जोड़ या प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है या जिसके परिणामस्वरूप शब्दों को अर्थहीन मानकर अस्वीकार कर दिया जाता है, उससे बचना होगा। इसके अलावा किसी अधिनियम में शब्दों को पढ़ना निर्माण के सभी नियमों के विपरीत है जब तक कि ऐसा करना बिल्कुल आवश्यक न हो। व्याख्या के नियम न्यायालयों को ऐसा करने की अनुमति नहीं देते हैं, जब तक कि प्रावधान निरर्थक या संदिग्ध अर्थ वाला न हो। न्यायालय, संसद के किसी अधिनियम में शब्दों को पढ़ने की हकदार नहीं हैं, जब तक कि इसके लिए स्पष्ट कारण अधिनियम के चारों कोनों में न पाया जाए।

3.3. किसी प्रावधान की व्याख्या करते समय न्यायालय केवल कानून की व्याख्या करता है, उस पर कानून नहीं बना सकता। यदि कानून के किसी प्रावधान का दुरुपयोग किया जाता है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है, तो यह विधायिका पर निर्भर है कि यदि आवश्यक समझा जाए तो वह इसमें संशोधन, परिवतर्न या निरस्त कर सकती है।

3.4. स्पष्ट आवश्यकता के मामले को छोड़कर और जब इसका कारण क़ानून के चारों कोनों में पाया जाता है, तब तक न्यायालय द्वारा एक कैसस ओमिसस प्रदान नहीं किया जा सकता है, लेकिन साथ ही कैसस ओमिसस का तुरंत अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए सभी किसी क़ानून या अनुभाग के कुछ हिस्सों को एक साथ समझा जाना चाहिए और अनुभाग के प्रत्येक खंड को संदर्भ और उसके अन्य खंडों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए ताकि किसी विशेष प्रावधान पर किया जाने वाला निर्माण पूरे क़ानून का एक सुसंगत अधिनियम बन सके। यह तब और अधिक होगा जब किसी विशेष खंड का शाब्दिक निर्माण स्पष्ट रूप से बेतुके या असंगत परिणाम देता है जो विधायिका द्वारा अपेक्षित नहीं हो सकता है।

शंकर रामचन्द्र अभ्यंकर बनाम कृष्णाजी दत्तात्रेय बापट, एआईआर (1970) एससी एल; के. इपेन चाको बनाम द प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी (पी) लिमिटेड, एआईआर (1976) एससी 2610; केर्तला राज्य बनाम के.एम. चारिया अब्दुल्ला एंड कंपनी, एआईआर (1965) एससी 1585; हरि शंकर एवं अन्य। वी. राव गिरधारी लाल चौधरी, एआईआर (1963) एससी 698; इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बनाम एमआईएस। प्राइम वॉटरहाउस और अन्य, एआईआर (1998) एससी 74; गुजरात राज्य और अन्य। वी. दिलीपभाई नल्हजीभाई पटेल और अन्य, जेटी (1998) 2

एससी 253; जाम्मा मस्जिद, मरकारा बनाम कोडिमनियांड्रा देवियाह और अन्य, एआईआर (1962) एससी 847; भारत संघ और अन्य। बनाम येडेम वास्को डी गामा के फिलिप टियागो डी गामा, एआईआर (1990) एससी 981; डॉ. आर. वेंकटचलम और अन्य। आदि. वि. उप. परिवहन आयुक्त एवं अन्य। आदि, एआईआर (1977) एससी 842; बिक्री कर आयुक्त, म.प्र. बनाम पॉपुलर ट्रेडिंग कंपनी, उज्जैन, (2000½ 5 एससीसी 515; छप्पन बनाम मोइदीन, 22 मैड 68 कोल्हापुर कैनसुगर वर्क्स लिमिटेड और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, एआईआर (2000) एससी 811, संदर्भित।

एजी बनाम सिल/ईएम, 33 एलजे। पूर्व 209; पोन्नामल बनाम अरुमोगम, (1905) एसी 390; एफ कोलोनियल शुगर रिफाइनिंग कंपनी बनाम ट्रूटिन, (1905) एसी 368; क्रॉफर्ड बनाम स्पूनर, (1846) 6 मूर पीसी एल; स्टॉक बनाम फ्रैंक जैप्स (टिप्टन) लिमिटेड, (1978) 1 सभी ईआर 948 (एचएल); लेनिघ वैली कोल कंपनी बनाम येनसावेज, 218 एफआर 547; आर्टेमिउ वी. प्रोकोपिउ, (1966) 1 क्यूबी 878; ल्यूक बनाम टीआरसी, (1966) एसी 557; फेंटन वी. हैम्पटन, 11 मूर पी.सी. 345; जोन्स बनाम स्मार्ट, आई टी.आर. 52; ग्रे बनाम पियर्सन 6 एच.एल. कैस. 61; एबली बनाम डेल 11 सी.बी. 378 और मिलर बनाम सोलोमन्स 7 एक्सच। 475, जी करने के लिए भेजा।

ऑक्सफ़ोर्ड डिक्शनमी, खंड I पृष्ठ 398; स्वीट एंड लॉ द्वारा लॉ डिक्शनरी बाउवियर द्वारा शब्दकोश का उल्लेख किया गया है।

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नं. 3488/2003.

मुम्बई उच्च न्यायालय के 1999 के क्रि.आर.ए.225 मे पारित निणर्य व आदेश दिनांक 29.8.2002 से।

साथ

सी.ए. नं. 3489, 3494-98 एवमं 3499 of 2003.

जी.एल.सांघी, वी.ए.मल्हौत्रा, एम.जी.बागेड, मनीष पाटील, चन्द्रशेखर अन्सारी, एच.के.पूरी, एस.के.पूरी, उज्जवल बनर्जी, आन्नदिता गुप्ता, आर.सन्थन क्रिश्ना, सी.एन.एस. मोहन राय व एच.ए. रिच्छुरा अपीलांट की अेार से।

वी.ए.बोबडे, रमेश पी.भटट, वी.एच.केदर, उदय उमेश ललीत, महेश अग्रवाल, रिश्री अग्रवाल, इ.सी.अग्रवाल, मनु किश्ना, एस.वी. महेश देशपाण्डे, अनिरूद्घ पी.माइ, बी.एम.कास्त, डां.कैलाश चन्द, एम.एन.सरार्फ, चिराग एम. सरार्फ, वी.डी.खन्ना, सत्यजीत शाहा, जुगलकिशोर व श्रीमति शारदा देवी पर्त्युत्तरदाता की अेार से।

न्यायालय का निणर्य जसिटस अरिजीत पसायत, द्वारा पारित किया गया।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 115 में संशोधन के प्रभाव से जुड़ा कानून का एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न इन अपीलों में शामिल है। चूँकि प्रश्न के उत्तर में कोई तथ्यात्मक निर्णय शामिल नहीं है, इसलिए उसका संक्षिप्त संदर्भ पर्याप्त होगा।1.7.2002 से लागू सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 (संक्षेप में 'संशोधन अधिनियम') की धारा 12(i) द्वारा, संहिता की धारा 115 में संशोधन किए गए थे। इन सभी अपीलों में, संबंधित उच्च न्यायालयों ने माना कि संशोधित धारा 115 के कारण, उनके समक्ष दायर किया गया पुनरीक्षण विचारणीय नहीं था, क्योंकि यदि पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले पक्ष के पक्ष में आदेश पारित किया गया होता, तो अंततः मुकदमे का निपटारा नहीं होता।

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने इन आधारों पर पुनरीक्षण आवेदनों को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए उनका निस्तारित करने में गलती की है। जो कि ये है (i)'संशोधित प्रावधान उन याचिकाओं पर लागू नहीं होते हैं जिन्हें संशोधन से पहले स्वीकार किया गया था, (ii) अपील और रिविजन समानांतर आधार पर खड़े हैं और अपीलकर्ता/आवेदक में निहित अधिकार हैं, जैसा भी मामला हो, और जैसा भी हो ऐसे संशोधित प्रावधानों का कोई उपयोग नहीं होगा, और (iii) निषेधाज्ञा के लिए आवेदन और इस तरह के संशोधन की

विषय वस्तु अभिव्यक्ति 'अन्य कार्यवाही' से संबंधित है और भले ही संशोधित प्रावधान लागू होते हैं, संशोधन का निपटान होगा ऐसी 'अन्य कार्यवाही' को अंतिम रूप से ख़ारिज. करना।

संशोधन अधिनियम की धारा 32(2)(i) के संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया गया है कि इसका कोई अर्थ नहीं है। विधायिका ने हमेशा सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 (संक्षेप में 'सामान्य खण्ड अधिनियम') की धारा 6 के संदर्भ में लंबित कार्यवाही को बचाया है और इसलिए, संशोधन की तारीख पर उच्च न्यायालय के समक्ष जो कार्यवाही लंबित थीं, वे स्पष्ट रूप से प्रभाव से बाहर हैं। भले ही तर्कों के लिए यह मान लिया जाए कि उस संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, यह स्पष्ट रूप से "कैसस ओमिसस" का मामला है।

जवाब में, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने तक प्रस्तुत किया कि किसी क़ानून के प्रावधानों के स्पष्ट अर्थ को पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए और प्रावधानों को पढ़ने से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि उच्च न्यायालय का आदेश "टेरा फ़रमा" पर है। जब भी विधायिका का इरादा लंबित कार्यवाहियों को संशोधित प्रावधानों के दायरे से बाहर रखने का था, तो विशेष रूप से ऐसा प्रावधान किया गया था। संहिता में 1976 में किए गए संशोधन का संदर्भ दिया गया है, जिसने नागरिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 (संक्षेप में 'पुराना संशोधन अधिनियम') की धारा 97(3)

में लंबित कार्यवाही को बचाया, सामान्य खण्ड अधिनियम की धारा 6 के क्रियान्वयन को खारिज किया ।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए धारा 115 के प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक होगा क्योंकि वे संशोधन से पहले और संशोधन के बाद मौजूद थे।

> "धारा 115 (संशोधन से पहले): (I) उच्च न्यायालय किसी भी मामले का रिकॉर्ड मांग सकता है जिसका निर्णय ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा किया गया है जो अपीलनीय नही है, और यदि ऐसा प्रतित होता है-
>
> (ए) उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, या
>
> (बी) इस प्रकार निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा है, या (सी) अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता के साथ कार्य किया है,
>
> उच्च न्यायालय मामले में ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे: बशर्ते कि उच्च न्यायालय, इस धारा

के तहत, किसी मुकदमे या आदेश की कार्यवाही के दौरान किए गए किसी भी आदेश, या किसी मुद्दे पर निर्णय लेने वाले किसी भी आदेश को बदल या उलट नहीं करेगा, सिवाय इसके कि - (ए) आदेश, यदि यह पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले पक्ष के पक्ष में किया गया होता, तो अंततः मुकदमे या अन्य कार्यवाही का निपटारा हो जाता, या

(बी) यदि आदेश को कायम रहने दिया जाता है, तो इससे न्याय में विफलता होगी या उस पक्ष को अपूरणीय क्षति होगी जिसके खिलाफ यह किया गया था।

(2) उच्च न्यायालय, इस धारा के तहत, किसी भी डिक्री या आदेश में बदलाव नहीं करेगा या उसे उलट नहीं देगा जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में अपील की जा सकती है।

स्पष्टीकरण: इस खंड में, अभिव्यक्ति "कोई भी मामला जो तय किया गया है: इसमें किसी मुकदमे या अन्य कार्यवाही के दौरान किया गया कोई भी आदेश, या किसी मुद्दे का निर्णय करने वाला कोई भी आदेश शामिल है।"

धारा 115 (संशोधन के बाद):

(1) उच्च न्यायालय किसी भी एसे मामले के अभिलेख को मांग सकेगा जिसका ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय ने विनिश्चय किया गया है और जिसकी कोइ अपील नहीं होती है आेर यिद यह प्रतित होता है कि-

(क) ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने एसी अधिकारिता का प्रयोग िकया है जो उसमें विधि दारा निहीत नहीं है, अथवा

(ख) ऐसा अधीनस्थ न्यायालय ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है जो इस प्रकार निहित है, अथवा

(ग) ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकाि◌ारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक अनियिमतता का प्रयोग करने अवैध रूप से या तात्विक अनियिमतता से कार्य किया है,

तो उच्च न्यायालय उस मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे:

परन्तु उच्च न्यायालय, किसी वाद या अन्य कायर्वाही के अनुक्रम में इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश में या कोइर् विवाधक विनिश्चित करने वाले किसी आदेश में तभी फेरफार करेगा या उसे उलटेगा जब ऐसा आदेश यदि वह पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया होता तो वाद या अन्य कायर्वाही का अंतिम रूप से

निपटारा कर देता।

(2) उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन किसी ऐसे डिक्री या आदेश में, जिसके विरूद्ध या तो उच्च न्यायालय मे या उसके अधीनस्थ् किसी न्यायालय में या उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में अपील होती है, फेरफार नहीं करेगा अथवा उसे नहीं उलटेगा।

(3) कोई पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कायर्वाही की रोक के रूप में प्रवतिर्त नहीं होगा सिवाय वहां के जहां ऐसे वाद या अन्य कायर्वाही को उच्च न्यायालय द्वारा रोका गया है।

स्पष्टीकरण: इस धारा में, "ऐसे मामले में अभिलेख को मंगवा सकेगा जिसका ऐसे उच्च न्यायायलय के अधीनस्थ् किसी न्यायालय ने विनिश्चय किया है।" अभिव्यकित के अन्तगर्त किसी वाद या अन्य कायर्वाही के अनुक्रम के अन्तगर्त किसी वाद या अन्य कायर्वाही के अनुक्रम में किया गया कोइर् आदेश या कोइर् विवाद्यक विनिश्चत करने वाला कोई भी आदेश भी है।

इन दोनो प्रावधानों की तुलना से पता चलता है कि जहां असंशोधित प्रावधान के परंतु क (ए) को उसकी समग्रता में बरकरार रखा गया है, वहीं संशोधित प्रावधानों में प्रावधान के खंड (बी) को हटा दिया गया है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संशोधन से पहले के अधिनियम में

संशोधन की शक्ति ज्यादा व्यापक थी। संशोधन द्वारा, धारा 115 रिविजन के तहत संशोधनों से निपटने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति पर कुछ सकारात्मक प्रतिबंध लगाए गए है। उक्त संशोधन से पहले, यह कड़ाई से आवश्यक नहीं था कि आक्षेपित आदेश या कायर्वाही अंतिम रूप निचले न्यायालय में निस्तारीत होने का परिणाम होगा। वास्तव में, इस शक्ति का प्रयोग किसी भी मामले में किया जा सकता है जहां मूल न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि हुई हो या जहां पर्याप्त रूप से अन्याय हुआ हो। पुराने संशोधन अधिनियम द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में लिस तथा कार्यवाहियों का अंतिम रूप से निर्णय को परिचित किया गया था। धारा 115 के तहत शक्ति के प्रयोग से पहले आवश्यक शर्तें हैं जिसमें पूवर्वती योग्यताएं शामिल हैं। वे प्रावधान खंड (ए) और (बी) थे। तार्किक रूप से, उच्च न्यायालय के पास उस आदेश को संशोधित/उलटने की suo motu शक्ति है जहां न्याय की पूर्णरूप से विफलता हुई हो या जहां उन पक्षों को अपूरणीय क्षति हुई हो जिनके खिलाफ यह किया गया था। ये शक्तियां खंड (बी) द्वारा बरकरार रखी गईं। हालाँकि, 1976 के बाद, इस शकित का प्रयोग कुछ हद तक सीमित हो गया था, लेकिन इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया था। दूसरे शब्दों में, 1976 के संशोधन के बाद भी उच्च न्यायालय उन मामलों में हस्तक्षेप कर सकता था जहां न्याय की विफलता या अपूरणीय क्षति हुई थी, कार्यवाही की प्रकृति में काफी बदलाव किया गया था और उच्च न्यायालय की स्वत: संज्ञान शक्ति बरकरार रखी गई

थी। यह अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति की प्रकृति में था। परिवर्तन शक्ति के प्रयोग में सीमाओं को .इंगित करने से संबंधित थे।

1976 में संशोधनों के बाद, 1999 में और 1976 में संशोधन से पहले भी, पुनरीक्षण शक्ति ऐसे मामले में प्रयोग योग्य थी जहां आदेश या डिक्री, जैसा भी मामला हो, अपील योग्य नहीं थी।

उप-धारा (2) जो पुराने संशोधन अधिनियम द्वारा पेश की गई थी वर्तमान संशोधन के बाद भी बरकरार रखा गया है, यह प्रावधान है कि जहां आदेश या डिक्री उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में अपील योग्य है वहां उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा।

यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि भारत के विधि आयोग ने धारा 115 को हटाने की सिफारिश की थी। विधि आयोग की राय में, धारा 115 के प्रावधान भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') के अनुच्छेद 227 के प्रावधानों के अनुरूप हैं। और यदि संपूर्ण धारा हटा दी जाती है तो वादियों पर किसी भी तरह का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। संसद की संयुक्त समिति ने इन सिफ़ारिशों पर चर्चा की और इस धारा में कुछ संशोधन करना ही उचित समझा। जिसके कारण पुराने संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 115 में संशोधन किया गया। समिति के विचार-विमर्श निम्नलिखित शब्दों में परिलक्षित होते हैं: "हालांकि, समिति का मानना है

कि, धारा 115 में निहित प्रतिबंधों के अलावा, अंतरिम आदेशों के खिलाफ संशोधन के लिए आवेदनों के दायरे पर एक समग्र प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। विधि आयोग द्वारा अपने चौदहवें और सत्ताईसवीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए की गइ, समिति ने सिफारिश की कि संहिता की धारा 115 को इस संशोधन के अधीन बरकरार रखा जाना चाहिए कि कोई भी संशोधन आवेदन किसी अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ तब तक नहीं होगा जब तक कि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी न हो,

> "पहला पहलू जिस पर विचार किया जाना है वह अपील और पुनरीक्षण से संबंधित दायरा है। कानून में यह बिल्कुल स्थापित स्थिति है कि अपील का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। लेकिन धारा 115 के तहत आवेदन करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि शंकर रामचन्द्र अभ्यंकर बनाम कृष्णाजी दत्तातेय बापट, एआईआर (1970) एससी में अपील और पुनरीक्षण को एक ही आधार पर खड़े होने कि टिप्पणी पर जोर दिया गया है परन्तु इस स्थित को स्वीकार किया जाना कठिन है। उक्त मामले में कि गइ टिप्पणियों को इस संदर्भ से बाहर पढ़ा जाना चाहिए। उस मामले में जो कहा गया वह उच्च न्यायालय की शक्ति के प्रयोग से संबंधित था, और उस

संदर्भ में अपील और पुनरीक्षण में विचार की प्रकृति का उल्लेख किया गया था। उस मामले में यह कभी नहीं माना गया कि अपील, पुनरीक्षण के बराबर है।

i. यदि आदेश आवेदक के पक्ष में किए गए, तो ऐसा होगा अंततः मुकदमे या अन्य कार्यवाही का निपटान करें; या

ii. यदि आदेश को कायम रहने दिया गया, तो इसके विफल होने की संभावना है न्याय या अपूरणीय क्षति का कारण।"

पहला पहलू जिस पर विचार किया जाना है वह अपील का संबंधित दायरा है और संशोधन. कानून में यह काफी अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि अपील का अधिकार एक मूल अधिकार है लेकिन बनाने में ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है धारा 115 के तहत आवेदन। हालांकि कुछ बातों पर बहुत जोर दिया गया था शंकर रामचन्द्र अभ्यंकर बनाम कृष्णाजी दलत्रय में टिप्पणियाँ बापट, एआईआर (1970) एससी । का तर्क है कि अपील और पुनरीक्षण एक ही स्थिति में हैं। आसन, प्रस्ताव को स्वीकार करना कठिन है। उक्त टिप्पणियों में कहा गया है मामले को संदर्भ से परे पढ़ा जा रहा है। उस मामले में क्या आयोजित किया गया था से संबंधित एक उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग, और उस संदर्भ में

की प्रकृति अपील एवं पुनरीक्षण में विचार का उल्लेख किया गया। उसमें यह बात कभी नहीं रखी गयी ऐसा मामला जिसमें अपील पुनरीक्षण के बराबर हो।

धारा 115 अनिवार्य रूप से उच्च न्यायालय के लिए अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी करने की शक्ति का एक स्रोत है। यह किसी भी तरह से अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी आदेश से पीड़ित वादी को राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार नहीं देता है। धारा 115 के तहत संशोधन करने का दायरा किसी मौलिक अधिकार से जुड़ा नहीं है।

संहिता की धारा 96 और 100 की जो कि अपील से संबधित है जिसकी तुलना संहिता की धारा 115 की भाषा की से की जा सकती है। जबकि पहले के दो प्रावधान विशेष रूप से अपील के अधिकार के रूप में प्रदान किये गये हैं, जबकि धारा 115 की तुलना में यह स्थिति नहीं ना ही ये पावधान एक दूसरे के सम्पूरक ही है। यह अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से पीड़ित व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने की बात नहीं करता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह पर्यवेक्षी शक्ति का प्रयोग करके अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति का एक स्रोत है।

एक अपील अनिवार्य रूप से मूल कार्यवाही की निरंतरता है और

मुकदमे की स्थापना के समय लागू प्रावधान अपील के संबंध में भी लागू होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वाद पक्ष के पास यह निहित अधिकार है, जिससे इसका उपचार पाप्त किया जा सके। जैसा कि प्रकरण के. इपेन चाको बनाम द प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी (पी) लिमिटेड, एआईआर (1976) एससी 2610 में देखा गया था, केवल उन मामलों में जहां निहित अधिकार शामिल हैं, एक कानून की व्याख्या ऐसे अधिकार को प्रभावित करने वाले के रूप में की जानी चाहिए संभावित रूप से सक्रिय हो। अपील का अधिकार केवल क़ानून द्वारा है। यह किसी कार्रवाई में प्रक्रिया का आवश्यक हिस्सा है, लेकिन "उच्च न्यायालय में प्रवेश करने और निचली अदालतों की त्रुटि के निवारण के लिए उसकी सहायता और हस्तक्षेप का आह्वान करने का अधिकार है। यह यह सर्वोपरि अधिकार प्रतीत होता है, अवर न्यायाधिकरण की प्रगति का हिस्सा है।" (वेस्टबरी देखें: एजी बनाम SILLEM, 33 जे.एक्स 209. अपील, जिसे पूर्ण रूप से तथाकथित कहा जाता है, वह है जिसमें प्रश्न है, क्या जिस न्यायालय से अपील की गई है उसका आदेश उस न्यायालय के समक्ष मौजूद मामलों पर सही था" (लॉर्ड डेवुइल पोन्नामल) वी. अरुमोगम,• 1905 एसी 390। अपील का अधिकार, जहां यह मौजूद है, मामले के सार रूप में और प्रक्रिया के रूप में नहीं (कोलोनियल शुगर रिफाइनिंग कंपनी बनाम एलआरटी, 1905 एसी 368)।

अपील का अधिकार वैधानिक है. अपील का अधिकार किसी को विरासत में नहीं मिलता. यह क़ानून द्वारा स्वीकार होने पर प्रदत्त व

निहित अधिकार बन जाता है। इस संबंध में अपील के अधिकार और वाद के अधिकार के बीच प्रयाप्र्त अंतर है। जहां प्रत्येक व्यक्ति को मुकदमा दायर करने का अंतर्निहित अधिकार है और इसकी स्थिरता के लिए कानून के किसी अधिकार की आवश्यकता नहीं है, वही अपील के लिए एसी आवश्यकता होती है। जैसा कि केरल राज्य बनाम के.एम.चारियाअब्दुल्ला एंड कंपनी, एआईआर (1965) एससी 1585, मामले में देखा गया था। अपील और पुनरीक्षण के अधिकार के बीच अंतर दो अभिव्यक्तियों में निहित अंतर पर आधारित है। अपील कार्यवाही की निरंतरता है; वास्तव में पूरी कार्यवाही अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष होती है और उसे निर्धारित वैधानिक सीमाओं के अधीन साक्ष्य की समीक्षा करने की शक्ति है। लेकिन पुनरीक्षण के मामले में, पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास जो भी शक्तियाँ हों या न हों, उसके पास साक्ष्य की समीक्षा करने की कोई शक्ति नहीं है, जब तक कि क़ानून स्पष्ट रूप से उसे वह शक्ति प्रदान न करे। इसे हरि शंकर और अन्य बनाम राव गिरधारी लाल चौधरी, एआईआर (1963) एससी 698 के मामले में चार जजों की बेंच ने नोट किया था कि अपील और पुनरीक्षण के बीच अंतर वास्तविक रूप से अन्तर विद`यमान है। अपील का अधिकार अपने साथ विधि के साथ-साथ तथ्य पर भी दोबारा सुनवाई का अधिकार रखता है, जब तक कि अपील का अधिकार प्रदान करने वाला क़ानून किसी तरह से दोबारा सुनवाई को सीमित नहीं करता है, जैसा कि संहिता के तहत उत्पन्न होने वाली द्वितिय अपीलों में किया गया है।

जबकि पुनरीक्षण की सुनवाई की शक्ति आम तौर पर एक वरिष्ठ न्यायालय को दी जाती है ताकि वह खुद को संतुष्ट कर सके कि किसी विशेष मामले का कानून के अनुसार निस्तारण किया गया है। यह मानने के लिए संहिता की धारा 115 का संदर्भ दिया गया था कि उक्त प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियां कुछ विशेष श्रेणियों के मामलों तक सीमित हैं। वहां अधिकार केवल क्षेत्राधिकार और क्षेत्राधिकार तक ही सीमित है।

जहां तक संशोधित प्रावधान के संचालन के क्षेत्र का संबंध है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संशोधित प्रावधान की भाषा स्पष्ट है।

कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय किसी ऐसे वैधानिक प्रावधान में कुछ भी नहीं पढ़ सकता है जो साधारण और स्पष्ट हो। क़ानून विधायिका का एक आदेश है। किसी क़ानून में प्रयुक्त भाषा विधायी मंशा का निर्धारक कारक है। शब्द और वाक्यांश ऐसे प्रतीक हैं जो सन्दर्भों के प्रति मानसिक सन्दर्भों को निदेशिर्त करते हैं। किसी क़ानून की व्याख्या करने का उद्देश्य इसे अधिनियमित करने वाले विधानमंडल के इरादे का पता लगाना है। (देखे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बनाम प्राइस वॉटरहाउस और अन्य, एआईआर (1998) एससी 74 देखें। विधायिका का इरादा मुख्य रूप से इस्तेमाल की गई भाषा से पता चलता है, जिसका अर्थ है कि जो कहा गया है उस पर

ध्यान दिया जाना चाहिए, ओर उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जो नहीं कहा गया है । इसके परिणामस्वरूप, शब्दों के समर्थन, जोड़ या प्रतिस्थापन से निकले अथ के माध्यम से शब्दों को अर्थहीन मानकर अस्वीकार कर दिया ऐसी व्याख्या से बचना चाहिए। जैसा कि क्रोफोर्ड बनाम स्पूनर (1846) 6 मूर पीसी में देखा गया है, न्यायालय, विधानमंडल को किसी अधिनियम की दोषपूर्ण शब्दावली के कारण सहायता नहीं कर सकता, हम जोड़ या सुधार नहीं कर सकते हैं, और व्याख्या द्वारा जो कमियां रह जाती हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं। (गुजरात राज्य और अन्य बनाम दिलीपभाई नाथजीभाई देखें) पटेल और अन्य, जेटी (1998) 2 एससी 253। किसी अधिनियम में शब्दों को पढ़ना व्याख्या के सभी नियमों के विपरीत है, जब तक कि ऐसा करना बिल्कुल आवश्यक न हो। (स्टॉक बनाम फ्रैंक जोन्स (टिपटन) लिमिटेड देखें, (1978) 1 इला ईआर 948 (एचएल)। व्याख्या के नियम न्यायालयों को ऐसा करने की अनुमति नहीं देते हैं, जब तक कि प्रावधान अर्थहीन या संदिग्ध अर्थ वाला न हो। न्यायालय किसी अधिनियम में शब्दों को पढ़ने का हकदार नहीं है. जब तक कि इसके लिए संसद के द्वारा स्पष्ट कारण अधिनियम सम्पूणर् रूप से न पाया जाए। (लॉर्ड लोरबर्न एल.सी. विकर्स संस एंड मैक्सिम लिमिटेड बनाम इवांस, (1910) एसी 445 (एचएल), जाम्मा मस्जिद, मरकारा बनाम कोडिमनियांड्रा डेवैया और अन्य, एआईआर (1962) एससी 847 में उद्धृत)।

सवाल यह नहीं है कि क्या माना जा सकता है और क्या इरादा किया गया है बल्कि सवाल यह है कि क्या कहा गया है। "क़ानून को यूलिड के प्रमेय के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए"। न्यायाधीश लर्न्ड हैंड ने कहा, "लेकिन शब्दों को उनके पीछे छिपे उद्देश्यों की कुछ कल्पना के साथ समझा जाना चाहिए"। (लेनिघ वैली कोल कंपनी बनाम येनसावेज, 218 एफआर 547 देखें)। इस दृष्टिकोण को भारत संघ और अन्य बनाम फ़िलिप टियागो डी गामा आफ वेदेमवेदेम वास्को डी गामा एआईआर (1990) एससी 981। में दोहराया गया था।

डॉ. आर. वेकटचलम व अन्य बनाम उप. परिवहन आयुक्त एवं अन्य, एआईआर (1977) एससी 842, यह देखा गया कि न्यायालयों को वैचारिक संरचना या योजना की अपनी पूर्व-कल्पित धारणाओं के आधार पर किसी प्रावधान के अर्थ के पूर्व निर्धारण के खतरे से बचना चाहिए जिसमें प्रावधान की व्याख्या कुछ हद तक की जाती है। वे व्याख्या की आड़ में विधायी कार्य को करने के हकदार नहीं हैं।

किसी प्रावधान की व्याख्या करते समय न्यायालय केवल कानून की व्याख्या करता है, उस पर कानून नहीं बना सकता। यदि कानून के किसी प्रावधान दुरूपयोग और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है, तो यह विधायिका पर निर्भर है कि यदि आवश्यक समझा जाए तो वह इसमें संशोधन, संशोधन या निरस्त कर सकती है। (बिक्री कर आयुक्त, मध्य

प्रदेश बनाम पॉपुलर ट्रेडिंग कंपनी, उज्जैन, [2000] 5 एससीसी 515 देखें। विधायीका की चूक, न्यायिक व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है।

व्याख्या के दो सिद्धांत - एक casus omissus से संबंधित और दूसरा क़ानून को समग्र रूप से पढ़ने के संबंध में अन्य - अच्छी तरह से निधारित प्रतीत होते है।पहले सिद्धांत के तहत स्पष्ट आवश्यकता के मामले को छोड़कर और जब इसका कारण क़ानून के समग्र रूप में पाया जाता है, तब तक न्यायालय द्वारा कैसस ओमिसस की पूर्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन साथ ही एक कैसस ओमिसस का तुरंत अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए और इसके लिए इसका उद्देश्य यह है कि किसी क़ानून या धारा के सभी हिस्सों को एक साथ समझा जाना चाहिए और धारा के प्रत्येक खंड को उसके संदर्भ और अन्य खंडों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए ताकि किसी विशेष प्रावधान पर किया जाने वाली व्याख्या पूरे का एक सुसंगत अधिनियम बन सके। यह तब और अधिक होगा जब किसी विशेष खंड का शाब्दिक निर्माण स्पष्ट रूप से बेतुके या असंगत परिणाम देता है जो विधायिका द्वारा अपेक्षित नहीं हो सकता है। आर्टेमियौ बनाम प्रोकोपियोउ (1966) 1 क्यूबी 878 में डैनैकवर्ट्स, एल.जे. ने कहा, "अनुचित परिणाम उत्पन्न करने का इरादा", "यदि कोई अन्य व्याख्या उपलब्ध है तो इसे किसी क़ानून में लागू नहीं किया जाना चाहिए"। जहां

शब्दों को शाब्दिक रूप से लागू करना "कानून के स्पष्ट इरादे को पराजित करेगा और पूरी तरह से अनुचित परिणाम देगा" हमें "शब्दों के साथ कुछ हिंसा करनी होगी" और इस तरह उस स्पष्ट इरादे को प्राप्त करना होगा और एक तर्कसंगत निर्माण करना होगा। (ल्यूक बनाम आईआरसी, (1966) एसी 557 में लॉर्ड रीड के अनुसार, जहां पृष्ठ 577 पर उन्होंने यह भी कहा: "यह कोई नई समस्या नहीं है, हालांकि ड्राफ्टिंग का हमारा मानक ऐसा है कि यह शायद ही कभी उभरता है"।

तब यह सच है कि, "जब किसी कानून के शब्दों के विस्तार से असुविधाएँ शायद ही कभी होती हैं, लेकिन जो अक्सर होती हैं कि शब्दों को उनकी पहुँच से अधिक न खींचे जो कैसस ऑमिसस का एक अच्छा कारण है और यह कि कानून का उद्देश्य बारंबार दुर्घटना के लिए है।" "लेकिन, दूसरी ओर," यह कोई कारण नहीं है, जब किसी कानून के शब्द पर्याप्त होते हैं एक ऐसी असुविधा का विस्तार करें जो शायद ही कभी हो रही हो, जिसे उन्हें विस्तारित नहीं करना चाहिए इसके साथ ही अगर ऐसा बार-बार होता है, क्योंकि ऐसा होता है, लेकिन शायद ही कभी" (फेंटन बनाम हैम्पटन आई आई मूर, पी.सी. 345 देखें)। कैसस ओमिनस को किसी गंभीर आवश्यकता के मामले को छोड़कर, व्याख्या द्वारा निमिर्त नहीं किया जाना चाहिए। जहा विधायिका की असावधानी के माध्यम से, या सिद्धांत के आधार पर, नियम यह है कि विशेष मामले में इस प्रकार

बिना प्रावधान के छोड़ दिया गया है, उसके अनुसार निपटाया जाना चाहिए कानून के लिए जैसा कि यह इस तरह के क़ानून से पहले अस्तित्व में था - कैसस ओमिसस एट ओब्लिवियोनी डेटस डिस्पोज़िशनि कम्युनिस ज्यूरिस रिलिनक्विटुर; जोन्स बनाम स्मार्ट (1 टी.आर. 52) में बुलर, जे. ने कहा, "एक कैसस ऑमिसस", "किसी भी मामले में कानून की अदालत द्वारा आपूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके लिए कानून बनाना होगा।" वसीयत, क़ानून और, वास्तव में, सभी लिखित की व्याख्या करने का सुनहरा नियम उपकरणों में इस प्रकार कहा गया है: "शब्दों के व्याकरणिक और सामान्य अर्थ का पालन किया जाना चाहिए जब तक कि इससे कुछ बेतुकापन या कुछ प्रतिकूलता या बाकी उपकरण के साथ असंगति न हो, इस स्थिति में शब्दों का व्याकरणिक और सामान्य अर्थ संशोधित किया जा सकता है, ताकि उस बेतुकेपन और असंगतता से बचा जा सके, लेकिन आगे नहीं" (ग्रे बनाम पियर्सन 6 एच.एल. कैस. 61 देखें)। हालाँकि, इस "सुनहरे नियम" के उत्तरार्ध को बहुत सावधानी से लागू किया जाना चाहिए। "अगर," जेर्विस, सी.जे. ने टिप्पणी की, "हमारे फैसले में इस्तेमाल किए गए सटीक शब्द स्पष्ट और स्पष्ट हैं, तो हम उन्हें उनके सामान्य अर्थ में समझने के लिए बाध्य हैं, भले ही यह मामले के बारे में हमारे दृष्टिकोण में, एक बेतुकेपन या स्पष्टता की ओर ले जाता है अन्याय। शब्दों को संशोधित या विविध किया जा सकता है जहां उनका आयात संदिग्ध या अस्पष्ट है। लेकिन हम विधायकों के कार्यों को तब मानते हैं

जब हम उपयोग किए गए सटीक शब्दों के सामान्य अर्थ से हट जाते हैं, केवल इसलिए कि हम देखते हैं, या कल्पना करते हैं, हम देखते हैं, एक बेतुकापन या प्रकट उनके शाब्दिक अर्थ के पालन से अन्याय" (एबली बनाम डेल 11, सी.बी. 378 देखें)।

इस समय, एक कहावत पर ध्यान देना आवश्यक होगा "Ad ea quae Frequentius Accidunt Jura Adobentur।"

> कानून ऐसे मामलों को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए और आमतौर पर बनाए जाते हैं जो दुर्लभ या आकस्मिक घटनाओं के बजाय बार-बार होने वाले मामलों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं; या, नागरिक कानून की भाषा में,, jus constitui oportet in his quoe 111 plurimum accidunt, non quoe ex inopinato; for, neque leges neque senatusconsulta ita scribi possunt ut omnes casus qui quandoque inciderint comprehendantur, sed sufficit ea quoe plerumque accident contineri; कानूनों को ऐसे शब्दों में नहीं लिखा जा सकता कि उनमें उत्पन्न होने वाले हर मामले को शामिल किया जा सके, लेकिन यह पर्याप्त है कि वे उन चीजों पर लागू हों जो अक्सर घटित होती हैं। सभी कानून

चीजों के सामान्य पाठ्यक्रम के लिए प्रदान करने के सिद्धांत पर आगे बढ़ते हैं, और इस सिद्धांत का बार-बार संदर्भ, रिपोर्टों में, तर्कों के उत्तर में पाया जाता है, अक्सर विशिष्ट रूप से उन्नत किया जाता है, कि किसी अधिनियम के शब्दों का कोई विशेष अर्थ नहीं हो सकता है , क्योंकि एक निश्चित आकस्मिकता में वह अर्थ काम कर सकता है जिसका परिणाम कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। मिलर बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका में सॉलोमन्स, (7 एक्सच. 475) यह तर्क दिया गया था कि संसद का इरादा यह नहीं हो सकता था कि एक यहूदी, हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठने से पहले, त्याग की शपथ में निर्धारित "एक ईसाई के सच्चे विश्वास पर" शब्दों का उपयोग करे। 6 जियो. 3, सी.53, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, दो न्यायाधीशों द्वारा दिए जाने पर एक ही शपथ लेने से इनकार कर सकता है, 1 जियो के तहत। 1 सेंट 2, सी.13, को पोपिश रिक्यूसेंट माना जाएगा, और इस तरह दंड के लिए उत्तरदायी होगा; और यह कहा गया था कि एक यहूदी के खिलाफ इन प्रावधानों को लागू करना सबसे बड़ा अत्याचार होगा। लेकिन बैरन पार्क ने इस तर्क का उत्तर इस प्रकार दिया: - "संभावित अधिकांश मामलों में - सभी सामान्य घटनाओं में - कानून किसी भी

हद तक असंगत या अनुचित नहीं है, इसके स्पष्ट शब्दों के अनुसार, यह मुझे एक अस्थिर प्रस्ताव लगता है ।", और प्राधिकरण द्वारा असमर्थित, यह कहना कि निर्माण हर मामले में भिन्न हो सकता है, क्योंकि एक संभव है लेकिन अत्यधिक असंभव है जिसमें कानून बड़ी गंभीरता के साथ काम करेगा, और न्याय की हमारी अपनी धारणाओं के खिलाफ उचित रूप से तर्क दिया गया है, कि उस विशेष मामले में इसे अलग-अलग किया जाना चाहिए, ताकि उस अन्याय को दूर किया जा सके - आगे नहीं।"

अपील एक वरिष्ठ न्यायालय में प्रवेश करने और निचली अदालत की त्रुटि के निवारण के लिए उसकी सहायता और हस्तक्षेप का आह्वान करने का अधिकार है। (वेस्टबरी सी., ए.जी. बनाम सिलेम, 10 एचएलसी 704 = 33 एलजे उदाहरण 209)।

"अपील", को ऑक्सफ़ोर्ड डिक्शनरी, वॉल्यूम 1, पृष्ठ 398 में परिभाषित किया गया है, पूर्व के निर्णय को उलटने या संशोधित करने की आशा में एक मामले को निचले से उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण में स्थानांतरित करने के रूप में। स्वीट द्वारा लॉ डिक्शनरी में, "अपील" शब्द को उच्च न्यायालय या अपील न्यायालय में प्रश्न प्रस्तुत करके

न्यायालय के एक गलत निर्णय को सुधारने के लिए की गई कार्यवाही के रूप में परिभाषित किया गया है, और यह जोड़ा गया है, विशेष रूप से तथाकथित कार्यवाही के अलावा, क्वीन्स बेंच डिवीजन और क्राउन मामलों की अदालत की राय के लिए बताए गए मामले, और त्रुटिपूर्ण कार्यवाही। बाउवियर द्वारा लॉ डिक्शनरी में एक अपील को समीक्षा और पुन: परीक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्न से बेहतर क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय से मामले को हटाने के रूप में परिभाषित किया गया है, और यह समझाया गया है कि अपने तकनीकी अर्थ में यह अलग है इसमें त्रुटि की एक रिट है, कि यह कानून और तथ्यों दोनों को समीक्षा और पुन: परीक्षण के अधीन करता है, जबकि उत्तरार्द्ध एक सामान्य कानून प्रक्रिया है जिसमें केवल पुन: परीक्षण के लिए कानून का मामला शामिल होता है; हालाँकि, यह जोड़ा गया है कि "अपील" शब्द का उपयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है ताकि इसमें तकनीकी रूप से अपील के रूप में वर्णित और सामान्य कानून त्रुटि की रिट दोनों शामिल हो सकें। जैसा कि श्री न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम अय्यर ने छप्पन बनाम मोइदीन, 22 मैड 68 पृष्ठ 80 में कहा है कि अपीलीय क्षेत्राधिकार के गठन के लिए दो चीजें आवश्यक हैं।

उच्च और निम्न न्यायालय के संबंध का अस्तित्व और पूर्व की ओर से, बाद वाले के निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति।

धारा 115 की उपधारा (2) संशोधन के बाद भी अपरिवर्तित बनी हुई है संशोधन अधिनियम द्वारा. एक नई उपधारा (3) जोड़ी गई है संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 115 में कहा गया है कि पुनरीक्षण अदालत के समक्ष मुकदमे या अन्य कार्यवाही पर रोक के रूप में कार्य नहीं करेगा, सिवाय इसके कि ऐसे मुकदमे या अन्य कार्यवाही पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी जाती है।

धारा 2 में 'आज्ञा' एवं 'आदेश' पदों को क्रमशः खण्ड (2) एवं (14) में परिभाषित किया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह बहुत कम मायने रखता है कि निर्णय को "आदेश" के रूप में स्टाइल किया गया है। यदि, वास्तव में, यह धारा 2(2) के तहत परिभाषा की शर्तों को पूरा करता है, तो यह एक डिक्री है और अपील योग्य हो जाती है। जो आदेश अपील योग्य नहीं होते हैं, वे आम तौर पर वे होते हैं जो कार्यवाही संबंधी होते हैं यानी कार्यवाही को विनियमित करने वाले अंतरिम या आकस्मिक आदेश होते हैं लेकिन मुकदमे में विवाद के किसी भी मामले का निर्णय नहीं करते हैं। आदेश 43 "आदेशों से अपील" से संबंधित है। ये अपीलें संहिता की धारा 104 के अंतर्गत आती हैं। उक्त धारा आदेशों की अपील से

संबंधित है और उन आदेशों को निर्दिष्ट करती है जिनसे अपील की जा सकती है। धारा 104 की उपधारा (2) कहती है कि उक्त धारा के तहत अपील में पारित किसी भी आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी। धारा 104 और आदेश 43 नियम 1 में अपील योग्य आदेशों की पूरी सूची है। एक आदेश जो धारा 2(2) के अंतर्गत एक डिक्री के बराबर है, वह धारा 104 के अंतर्गत नहीं आता है और एकमात्र लागू धारा धारा 96 है। धारा 104 के खंड (ए) से (एफ) को मध्यस्थता अधिनियम 1940 द्वारा हटा दिया गया था। धारा 105 किससे संबंधित है अन्य आदेश. यह, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी भी आदेश से संबंधित है यानी अपीलीय और गैर-अपीलीय आदेश। यह निषेधाज्ञा की प्रकृति में है कि अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के अलावा, मूल या अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी; लेकिन जहां किसी डिक्री के खिलाफ अपील की जाती है, किसी भी आदेश में कोई त्रुटि, दोष या अनियमितता, जो मामले के निर्णय को प्रभावित करती है, को अपील के ज्ञापन में आपत्ति के आधार के रूप में रखा जा सकता है। उपधारा (2) रिमांड के मामले से संबंधित है। यह धारा, वास्तव में, दो चीजों पर विचार करती है यानी (I) डिक्री से नियमित अपील; और (2) अंतरिम आदेश से संबंधित आपत्ति स्वीकार करने से संबंधित प्रावधान। आदेश 43 नियम 1 धारा 104 का अभिन्न अंग है।

धारा 115 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जोर इस सवाल पर है कि क्या पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले पक्ष के पक्ष में आदेश ने मुकदमे या अन्य कार्यवाही को अंतिम रूप दे दिया होगा। यदि उत्तर 'हाँ' है तो पुनरीक्षण स्वीकार्य है। लेकिन इसके विपरीत, यदि उत्तर 'नहीं' है तो पुनरीक्षण विचारणीय नहीं है। इसलिए, यदि आक्षेपित आदेश अंतरिम प्रकृति का है या अंतिम रूप से मामले का निर्णय नहीं करता है, तो पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा। विधायी मंशा एकदम स्पष्ट है। वे आदेश, जो प्रकृति में अंतरिम हैं, धारा 115 के तहत संशोधन का विषय नहीं हो सकते हैं। पुराने संशोधन अधिनियम की धारा 97(3) और संशोधन अधिनियम की धारा 32(2)(i) की भाषा में उल्लेखनीय अंतर है। . जबकि पूर्व में, संशोधन लागू होने से पहले स्वीकृत या लंबित आवेदनों को बचाने का स्पष्ट विधायी इरादा था। धारा 32(2)(i) में ऐसा आशय स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। संशोधन प्रक्रियाओं से संबंधित है। किसी भी व्यक्ति के पास प्रक्रिया के दौरान निहित अधिकार नहीं है। उसे केवल निर्धारित तरीके से आगे बढ़ने का अधिकार है। यदि वैधानिक परिवर्तन द्वारा प्रक्रिया के तरीके में बदलाव किया जाता है, तो पार्टियों को बिना किसी अपवाद के, बदले हुए तरीके के अनुसार आगे बढ़ना होगा, जब तक कि कोई अलग शर्त न हो।

सामान्य खण्ड अधिनियम की धारा 6 का वहां कोई अनुप्रयोग नहीं

है संहिता की धारा 115 के तहत संशोधन की मांग करने वाले पक्ष के लिए कोई वास्तविक निहित अधिकार उपलब्ध नहीं है। कोल्हापुर केनसुगर वर्क्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर (2000) एससी 811, यह देखा गया कि यदि लंबित कार्यवाही के पक्ष में बचत खंड के बिना किसी क़ानून के प्रावधान को बिना शर्त हटा दिया जाता है, तो सभी कार्रवाइयां वहीं रुक जानी चाहिए जहां चूक उन्हें मिलती है, और यदि चूक प्रभावी होने से पहले अंतिम राहत नहीं दी गई है, बाद में इसे देने की कोई गुंजाइश नहीं है। सामान्य खण्ड अधिनियम की धारा 6 को लागू करके या विशेष प्रावधान बनाकर इस स्थिति में संशोधन किया जाता है। भविष्य और अतीत के संबंध में निरसन या विलोपन का संचालन काफी हद तक लागू बचत पावधान पर निर्भर करता है। ऐसे मामले में जहां क़ानून में एक विशेष प्रावधान हटा दिया गया है और उसके स्थान पर लंबित कार्यवाही के पक्ष में बचत खंड के बिना उसी आकस्मिकता से निपटने वाला एक और प्रावधान पेश किया गया है, तो यह उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि विधायिका का इरादा यह है कि लंबित कार्यवाही जारी रहेगी लेकिन नए प्रावधान के तहत उसी उद्देश्य के लिए नई कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

ऊपर जो कहा गया है, उसके मद्देनजर अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि रिविजन पाथर्ना-पत्रों की अस्वीकार्यता के बारे में उच्च न्यायालय का

निष्कर्ष सही था।

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि भले ही पुनरीक्षण आवेदनों को सुनवाई योग्य नहीं माना जाता है, संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत चुनौती देने पर रोक नहीं होनी चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ताओं को उपाय का लाभ उठाने का अवसर दिया जा सकता है।

यदि किसी व्यक्ति के लिए किसी क़ानून के तहत कोई उपाय उपलब्ध है तो वह स्वतंत्रत है इसका लाभ उठाने के लिए जो दिया जाना आवश्यक है। यदि अपीलकर्ता इस उपाय का लाभ उठाते हैं तो कानून के अनुसार निपटाया जाएगा।

अपीलें खारिज की जाती हैं। कोई कोस्ट नही.

एन.जे. अपीलें खारिज

यह अनुवाद आटिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विनोद कुमार वाजा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह नि्रणय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सिमित उपयोग के लिए स्थानिय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारित उदेश्यों के लिए, निणर्य का अंग्रेजी संस्करण ही पामाणिक होगा और निष्पादन और कायान्वयन के उदेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।